सेना-सिविल तालमेल ही नई ताकत

राजनाथ सिंह का बयान

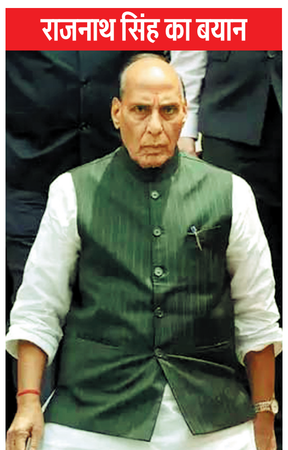

संयुक्त प्रयासों से ही मजबूत होगा भारत का रक्षा तंत्र

साइबर युद्ध से रक्षा तक राजनाथ ने दिया नया विजन

संयुक्त प्रशिक्षण और साझा जिम्मेदारियों पर जोर

नई दिल्ली 03 अगस्त. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत रक्षा प्रणाली में सैन्य और सिविल कर्मचारियों के बीच सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक घटकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है.

श्री सिंह ने सोमवार को यहां 85वें सशस्त्र सेना मुख्यालय (एएफएचक्यू) सिविलियन सेवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि सैन्य और नागरिक सेवाएं दोनों ही 'राष्ट्र सर्वोपरि% के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं और जब उद्देश्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री की इस अपील का उद्देश्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा तंत्र में अधिक तालमेल स्थापित करना, संस्थागत स्मृति, स्थिरता और नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करना है.

श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और प्रशासनिक सहयोग अलग-अलग रास्तों पर नहीं चल सकते. उन्होंने कहा कि संयुक्त और एकीकृत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ नीति, प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रक्रियाओं, रसद और संस्थागत ज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी. उन्होंने नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच आपसी संपर्क को और बढ़ाने के महत्व पर बल दिया.

> रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य अधिकारियों को संचालन अनुभव, कमान दृष्टिकोण और युद्ध की समझ होती है जबकि नागरिक अधिकारी प्रशासनिक निरंतरता, नीतिगत अनुभव, सरकारी प्रक्रियाओं की समझ और संस्थागत स्मृति के माध्यम से योगदान देते हैं. जब ये शक्तियां आपस में मिलती हैं, तो निर्णय लेना अधिक संतुलित और प्रभावी हो जाता है. उन्होंने %साइबर युद्ध% का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन सेवा के अधिकारी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए रक्षा-विशिष्ट साझा साइबर उपकरण विकसित करें, तो यह रक्षा बलों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य इतिहास के अध्ययन के लिए एक मंच विकसित किया जा सकता है, जिसमें नागरिक परिप्रेक्ष्य से इसके विश्लेषण से नए विचार व दृष्टिकोण विकसित हो सकें. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता का लाभ उठाकर वायु सेना मुख्यालय के नागरिक सेवा अधिकारी रक्षा क्षेत्र में अधिक सार्थक योगदान दे सकेंगे.

उज्बेक के विदेश मंत्री ने मुर्मु से की मुलाकात

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने पर बनी सहमति

नई दिल्ली, 03 अगस्त. उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. बैठक के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी साझेदारी को गहरा करने का अवसर प्रदान करता है.

राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं, जो पुराने व्यापार मार्गों से जुड़े हैं. राष्ट्रपति सचिवालय ने आगे लिखा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी फायदेमंद साझेदारी को गहरा करने का मौका देता है. इससे पहले दिन में सैदोव बख्तियार ओडिलोविच भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे. उनके स्वागत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव का नई दिल्ली में आधिकारिक दौरे पर आने पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत है. सैदोव भारत सरकार के निमंत्रण पर तीन से पांच अगस्त तक भारत में रहेंगे.

राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात के बाद वे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी बातचीत करेंगे. इसके अलावा, वे नई दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा होगी.

'गोल्डन रिंग' विकास का हब बनेगा

एआई और क्लाउड से बढ़ेगा निवेश

नई दिल्ली 3 अगस्त. भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से हो रहे विस्तार के बीच सोमवार को जारी एक नई रिपोर्ट ने रोजगार और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बड़ी उम्मीद जगाई है.

स्क्वायर यार्ड्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रस्तावित करीब 9,030 मेगावाट क्षमता वाली डेटा सेंटर परियोजनाएं वर्ष 2030 तक लगभग 4.33 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष नौकरियां पैदा कर सकती हैं. साथ ही आवासीय क्षेत्र में करीब 19.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त मांग भी पैदा होने का अनुमान जताया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत फिलहाल दुनिया के कुल डिजिटल डेटा का करीब 20 प्रतिशत उत्पादन करता है, लेकिन वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता में उसकी हिस्सेदारी महज 4 प्रतिशत है. यह अंतर देश में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की बड़ी संभावनाओं को दर्शाता है. रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन में तेजी आने से डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ रहा है. इससे देश की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा होने की उम्मीद है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित रियल एस्टेट विकास की नई लहर को जन्म देगा. विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा सेंटर सिर्फ डिजिटल सेवाओं तक सीमित नहीं रहते. ये अपने आसपास बिजली आपूर्ति नेटवर्क, फाइबर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और व्यावसायिक सेवाओं का विकास भी आकर्षित करते हैं. समय के साथ ये क्षेत्र नए शहरी आर्थिक केंद्रों का रूप ले लेते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े डेटा सेंटर परिसरों के आसपास 5 से 15 किलोमीटर का क्षेत्र सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा.

रिपोर्ट

- **2030 तक भारत में 4.33 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद**
- **5.4 करोड़ वर्गफुट से अधिक आवासीय मांग पैदा हो सकती है**

चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में जवाब दे सरकार: खरगे

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चढावा चोरी तथा छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर संसद में जवाब देने की मांग की है. श्री खरगे ने सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार सदन में बहस से बच रही है और उसका यह प्रयास संसद, लोकतंत्र और जनता का अपमान है. उनका कहना था कि श्री मोदी और श्री शाह संसद में आकर बताएं कि चढावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन तथा आंसू गैस के इस्तेमाल की नौबत क्यों आई. उन्होंने कहा, लोकतंत्र में बहस होती है और विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है.

जुलाई में भारतीय रेल की माल ढुलाई 9% बढ़ी

■ 141.3 मिलियन टन से अधिक माल ढोया ■ लौह अयस्क की ढुलाई 22.2% बढ़ी

नई दिल्ली 3 अगस्त. भारतीय रेल ने जुलाई 2026 में माल ढुलाई और यात्री सेवाओं दोनों क्षेत्रों में मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया. इस दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन माल ढुलाई की, जो जुलाई 2025 के 129.7 मिलियन टन के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक है.

माल ढुलाई में वृद्धि, यात्रियों की बढ़ती आवाजाही, बेहतर राजस्व अर्जन और आवश्यक वस्तुओं की अधिक ढुलाई भारतीय रेल की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और देशभर में भरोसेमंद परिवहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है. जुलाई 2026 में कई प्रमुख कमोडिटी समूहों की ढुलाई में सालाना आधार पर अच्छी वृद्धि दर्ज की गई. लौह अयस्क की ढुलाई 22.2 प्रतिशत, उर्वरक की 12प्रतिशत, कोयले और अनाज की ढुलाई 11.5 प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई 12.1 प्रतिशत बढ़ी. यह वृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र से मजबूत मांग का संकेत देती है.

> पश्चिम-मध्य रेलवे का माल ढुलाई राजस्व 23 प्रतिशत और दक्षिण-पूर्व रेलवे का 10.33 प्रतिशत बढ़ा. जुलाई 2026 में भारतीय रेल ने 63.35 करोड़ यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई, जबकि जुलाई 2025 में यह संख्या 62.19 करोड़ थी. उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों श्रेणियों में यात्री यातायात बढ़ा, जो देशभर में रेल यात्रा की बढ़ती मांग और बेहतर कनेक्टिविटी का संकेत है. भारतीय रेल माल ढुलाई की लॉजिस्टिक सुविधाओं को मजबूत करने, यात्री सेवाओं में सुधार और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है. परिचालन दक्षता बढ़ाने, क्षमता विस्तार और ग्राहक-केंद्रित पहलों के जरिए रेलवे देश की आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और करोड़ों यात्रियों के सुगम आवागमन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

थर्मल पावर संयंत्रों में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेल ने जुलाई 2026 में विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 20 प्रतिशत बढ़ाई. इससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और बिजली क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में रेलवे की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है.

माल ढुलाई में वृद्धि से जुलाई 2026 में रेलवे को जुलाई 2025 की तुलना में 1,137 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ, जो 8 प्रतिशत की वृद्धि है. जोनल रेलवे में पूर्व-मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे ने 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की.

एक नजर में

उद्धव ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों को फटकारा

मुंबई. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के ठाणे-कल्याण के पदाधिकारियों को आपसी लड़ाई के लिए जमकर फटकार लगाई. पार्टी पदाधिकारियों की यह आपसी लड़ाई कुछ दिनों पहले कल्याण लोकसभा क्षेत्र में अनुभवी कार्यकर्ताओं को अचानक पार्टी से निकाले जाने की वजह से शुरू हुई थी. पार्टी के पुराने वफादार और संभावित नए पदाधिकारी नेतृत्व में अपनी जगह बनाने को लेकर आपस में भिड़ गए, तो यह अंदरूनी कलह पार्टी नेतृत्व के सामने तीखी बहस में बदल गई. इस दौरान विधायक मिलिंद नार्वेकर, ठाणे जिला प्रमुख केदार डिघे और पूर्व विधायक विलास पोटनिस जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. श्री ठाकरे ने अपनी मौजूदगी में जब यह गुटबाजी देखी, तो उन्होंने झगड़ते नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि वे बड़े राजनीतिक परिदृश्य को भूल गए हैं. श्री ठाकरे ने देशभर में सरकार के खिलाफ हो रहे जबरदस्त विरोध-प्रदर्शनों की तुलना अपनी अंदरूनी लड़ाई से करते हुए बैठक में मौजूद लोगों को खरी-खोटी सुनाई.

31 साल बाद ढहा भाजपा का गढ़

पटना, 03 अगस्त. चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड के रूप में देशभर में पहचान बना चुके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है.

▸ **प्रशांत किशोर ने रचा इतिहास**

इस जीत के साथ उन्होंने भाजपा के उस मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया, जहां पिछले 31 वर्षों से पार्टी का लगातार कब्जा था. जन सुराज पार्टी की यह पहली विधानसभा जीत है और इससे पार्टी ने बिहार की राजनीति में अपनी औपचारिक उपस्थिति दर्ज करा दी है. बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी. नितिन नवीन इस सीट से लगातार पांच बार विधायक रहे, जबकि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी चार बार इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे. इस तरह लगातार नौ चुनावों से भाजपा के कब्जे वाली सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है. किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ. उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से भी जुड़े रहे.

बृजभूषण के फैसले को चुनौती देंगी विनेश

यौन उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत ने किया है बरी

नई दिल्ली, 03 अगस्त. देश की जानी मानी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सोमवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के आरोपों में निचली अदालत द्वारा बरी किये जाने वाले फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती दी जायेगी.

सुश्री विनेश ने जोर देकर कहा कि न्याय के लिए उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. उनका यह बयान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार द्वारा छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में श्री बृजभूषण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी किए जाने के कुछ घंटों बाद आया. अदालत का विस्तृत फैसला अभी जारी नहीं हुआ है. सुश्री विनेश और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संयुक्त पोस्ट में कहा कि शिकायतकर्ताओं ने पहले ही अपनी कानूनी टीम को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है.

हस्तियों के ट्वीट

आप आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई. बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए. उनको बहुत-बहुत बधाई. भाजपा की ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है. चंदा चोरी, पेपर लीक, ई 20... मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है. अहंकार टूटता जा रहा है. देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है.

नीति आयोग ने अपने ऑफिसियल अकाउंट ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा की नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम और राज्य नोडल अधिकारी डॉ. राका सक्सेना ने नीति आयोग की टीम के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का दौरा किया. इस दौरे का मकसद कृषि, ब्लू इकोनॉमी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और उद्यमिता, तथा स्वास्थ्य और कल्याण जैसे अहम क्षेत्रों पर बातचीत करना था.

NITI AAYOG

आज का इतिहास

- **1791:** सिस्टोवा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ओटोमन-हैब्सबर्ग युद्ध समाप्त हो गया.
- **1862:** अमेरिकी सरकार ने अपना पहला आय कर एकत्र करने का आदेश दिया.
- **1870:** ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की.
- **1886:** कोलंबिया ने आज के दिन ही देश का संविधान पारित किया.
- **1914:** इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी.

सेशेल्स में 1008 घर बनाएगी एनबीसीसी

75 मिलियन डॉलर की परियोजना से मिलेगा किफायती आवास

नई दिल्ली, 03 अगस्त. एनबीसीसी ने सेशेल्स गणराज्य सरकार के साथ 1008 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सेशेल्स गणराज्य सरकार के साथ ऑरोर द्वीप आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सेशेल्स में संबंधित अवसंरचना सहित 1008 किफायती आवासीय इकाइयां शामिल हैं.

महामहिम सेबेस्टियन पिल्लै, उपराष्ट्रपति, सेशेल्स गणराज्य और डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की गरिमामई उपस्थिति में बुधवार को इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते पर श्री जोसेफ फ्रांस्वा, भूमि, आवासन एवं अवसंरचना विभाग के राज्य सचिव, सेशेल्स गणराज्य सरकार तथा श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (इंजी.), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए.

योगी ने दिया जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा पर बल

लखनऊ, 3 अगस्त. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के शुभारंभ पर सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि विधायिका आम जनता की आवाज उठाने का सर्वोच्च मंच है और सदन के समय का उपयोग जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए किया जाना चाहिए. सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका किसान, युवा, महिला तथा समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, समीक्षा और उनके समाधान का माध्यम है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठाकर उनके समाधान का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद की इसी परंपरा के माध्यम से प्रदेश में अनेक सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके हैं.

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

Smart City

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

Sr.No.	Title and Tender ID No.	Bid Due Date	Bid Opening Date
01	Renovation works including Civil, Interior and Furniture works at Sant Tukaram Maharaj Natyagruh **2026_ASCDC_1324516_1**	10-08-2026 5.00 PM	11-08-2026 5.00 PM

The tender document can be downloaded from
https://www.mahatenders.gov.in
Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

संबोधन ▸ खनन, टेक्सटाइल, हेल्थकेयर और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर मौजूद हैं

भारत-उज्बेक के बीच व्यापार बढ़ाने की अपार संभावनाएं

नई दिल्ली, 03 अगस्त. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं.

उन्होंने कहा कि खनन, टेक्सटाइल, हेल्थकेयर और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के बड़े अवसर मौजूद हैं. उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजिज कुद्रतोव की मौजूदगी में भारत-उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने दोनों देशों के कारोबारियों को साथ मिलकर निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. गोयल ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आपसी भरोसे, सम्मान और साझा समृद्धि के विजन पर आधारित रणनीतिक साझेदारी व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अवसर उपलब्ध कराती है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद संभावनाओं का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है.

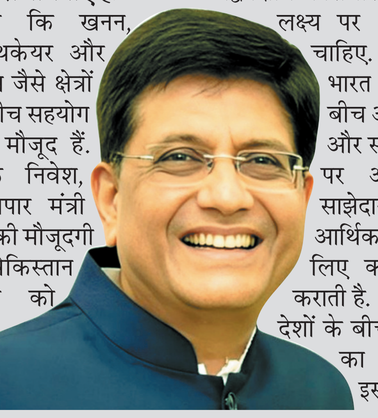

> **1.5 अरब डॉलर के व्यापार में विस्तार की गुंजाइश**
>
> केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापार और निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान जरूरी है. गोयल ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान के लिए केवल एक बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार नहीं है, बल्कि भरोसेमंद साझेदार, कुशल और युवा कार्यबल तथा इनोवेशन आधारित विकास के लिए मजबूत मंच भी उपलब्ध कराता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के कारोबारियों के बीच साझेदारी से आर्थिक संबंधों को नई दिशा मिल सकती है.
>
> **निवेश संधि से बढ़ेगा कारोबारियों का भरोसा**
>
> भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल में हुई द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि यह समझौता निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा. इससे दोनों देशों के व्यवसायों को एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. गोयल ने उन क्षेत्रों की भी पहचान की, जहां दोनों देशों के बीच सहयोग की मजबूत संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान का खनन क्षेत्र भारतीय निवेशकों के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करता है.

देश में 1.25 करोड़ से अधिक मामलों की ई- फाइलिंग-नई दिल्ली, 3 अगस्त. सरकार ने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), ई-सेवा केंद्र, ई-भुगतान और मोबाइल एप जैसी डिजिटल सेवाएं लागू की गई हैं जिसके तहत 30 जून तक देश भर में 1,25,87,329 मामलों की ई-फाइलिंग की जा चुकी है.

कार्यालय नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.)

(Subhash ward, Narsinghpur Phone: 07792-230402) Email: cmonarsinghpur@mpurban.gov.in)

पत्र क्रं. 1480/ ई-टेण्डर/ 2026-27 — नरसिंहपुर दिनांक :- 03/08/2026

तृतीय निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

स. क्रं.	निविदा आमंत्रण क्रमांक	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1		2	3	4	5	6
1.	तृतीय आमंत्रण	2026_UAD_501520_3 04/08/2026	निकाय अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण पाईप लाईन को बदलने का कार्य।	09 माह 13860560.00	12500.00 69310.00	21/08/2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://www.mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर